भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



₩ 281] No. 281] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, मई 1, 1997/वैशाख 11, 1919 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 1997/VAISAKH 11, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1997

का॰ आ॰ 362 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ) और नैशनल लिब्नेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी) को, जिन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 3-4-1997 की अधिसूधना सं॰ का॰ आ॰ 291 (अ) और 292 (अ) द्वारा विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जा चुका है, विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं ''विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण'' गठित करती है। अधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमिति श्री जे॰ के॰ मेहरा से मिलकर बनेगा।

[फा॰ सं॰ 9/27/97~एन० ई॰-[]

जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1997

S. O. 362 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Govt. hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the All Tripura Tiger Force (ATTF) and National Liberation Front of Tripura (NLFT) as unlawful associations declared as such by the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide No. S. O. 291 (E) and 292 (E) dated 3-4-1997 respectively. The Tribunal shall consist of Mr. Justice J. K. Mehra Judge of the Delhi High Court.

[F. No. 9/27/97-NE. I]

G. K. PILLAI, Jt. Secv.

1076 GI/97